



विकिसीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार

द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800-345-1111



माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का शुभारंभ किया

प्रत्येक नागरिक से तिरंगे को गर्वपूर्वक प्रदर्शित करने तथा इसके साहस, एकता और देशभक्ति के मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान

ग्रेट निकोबार विकास परियोजना भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगी और विकास के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी: माननीय उपराष्ट्रपति



श्री विजय पुरम, 9 अगस्त (पीआईबी)

माननीय उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में, श्री विजय पुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का उद्घाटन किया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) के सभागार में आयोजित राज्य समारोह एवं ‘वंदे मातरम्’ पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम’ को संबोधित करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ करने के लिए इन ऐतिहासिक द्वीपों से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तिरंगे के इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं।

महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अमर शब्दों को याद करते हुए श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भारती द्वारा ‘मणि कोडी’ का उत्सव भारतीय आत्मा के शाश्वत साहस और भारत माता के ध्वज की महिमा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ प्रत्येक नागरिक को एक राष्ट्रीय ध्वज, एक मातृभूमि और एक साझा नियति के अंतर्गत एकजुट करके इसी भावना को आगे बढ़ाता है।

काले पानी की भयावह सजा सहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों

को याद करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भारत के केवल एक भौगोलिक हिस्से से कहीं अधिक हैं, वे बलिदान की पवित्र भूमि हैं। उन्होंने वीर विनायक दामोदर सावरकर और उन अनगिनत देशभक्तों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने सेल्यूलर जेल में कष्ट सहें, और कहा कि उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

माननीय उपराष्ट्रपति ने याद किया कि 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के ‘करो या मरो’ के आह्वान ने लाखों भारतीयों को जागृत किया और स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति प्रदान की। उन्होंने तिरंगे के इतिहास में द्वीपों के विशिष्ट स्थान पर भी प्रकाश डाला और याद किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर, 1943 को यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक क्षण था।

‘हर घर तिरंगा’ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से तिरंगे को गर्वपूर्वक प्रदर्शित करने और इसके द्वारा प्रदर्शित

शेष पृष्ठ 4 पर

माननीय उपराष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त

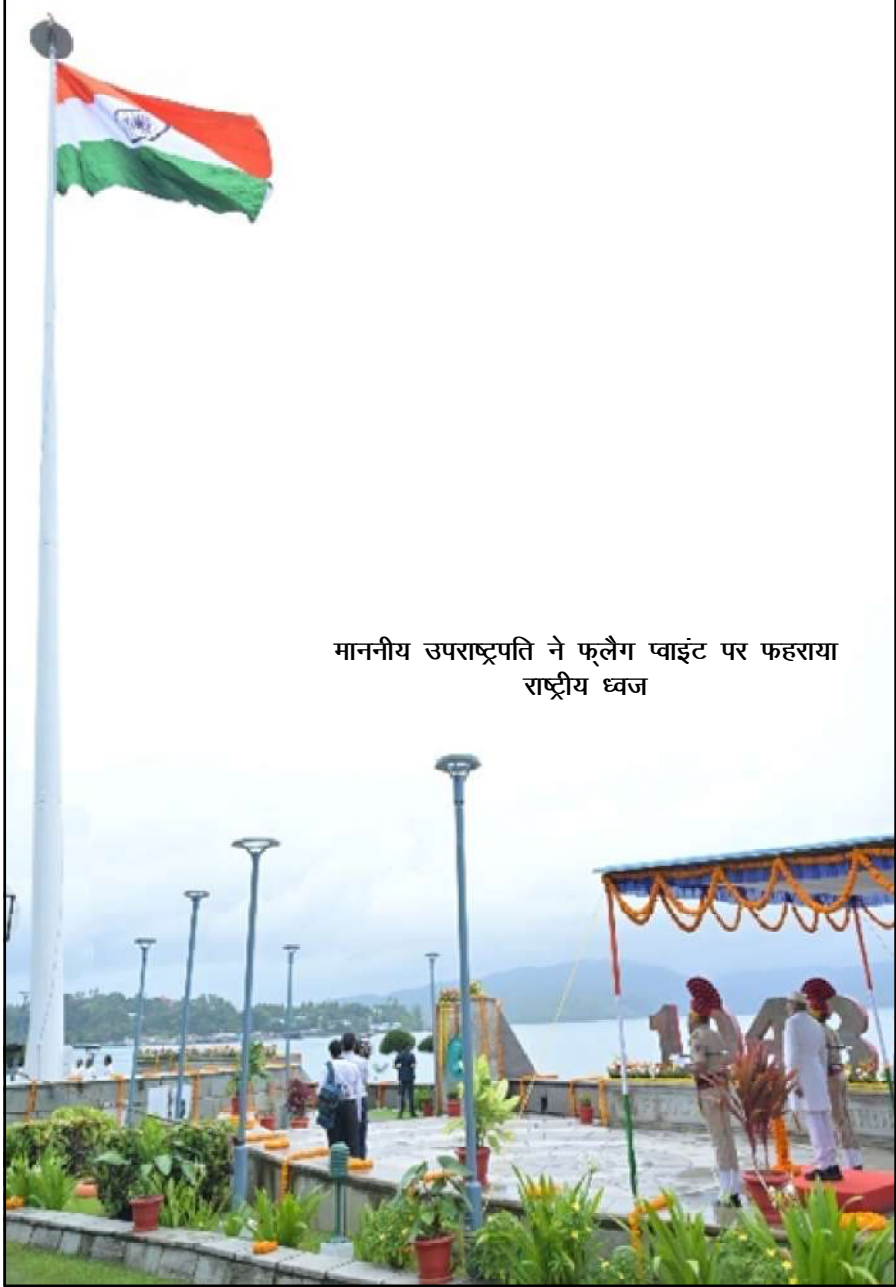
माननीय उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ रहे।

माननीय उपराष्ट्रपति ने



गन प्वाइंट क्षेत्र और स्मृतिका संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्हें द्वीप के समृद्ध इतिहास और इसके भविष्य के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत माननीय उपराष्ट्रपति ने फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया



माननीय उपराष्ट्रपति ने फ्लैग प्वाइंट पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त

माननीय उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत श्री विजय पुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर, 1943 को तिरंगा फहराकर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति ने उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के ‘करो या मरो’ के आह्वान से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के संघर्ष में राष्ट्र को एकजुट किया। उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।



इस कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास

एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन को द्वीपसमूह की यात्रा पूर्ण होने पर दी गई स्नेहपूर्ण विदाई

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त

माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन को आज शाम मुख्यभूमि के लिए प्रस्थान करने पर स्नेहपूर्ण विदाई दी गई। उन्होंने 8 और 9 अगस्त, 2026 को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया।

माननीय उपराष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), अण्डमान



निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्ती, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव, पुलिस महानिदेशक श्री रविंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष, जिला परिषद दक्षिण अण्डमान श्री पी. उमर, अध्यक्ष, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद श्रीमती एम. वसंता तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदाई दी।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह —————पृष्ठ 1 का शेष



देशभक्ति, एकता तथा सामूहिक जिम्मेदारी के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, “भारत एक है और हमेशा एक रहेगा।”

माननीय उपराष्ट्रपति ने द्वीपों को ‘विविधता में एकता’ और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का जीवंत उदाहरण बताया तथा उनकी समृद्ध जनजातीय विरासत और संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हाल की प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना भारत की समुद्री क्षमताओं, संपर्क और आर्थिक अवसरों को और मजबूत करेगी तथा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखेगी।

भारत की शांति और उदारता की परंपरा के साथ राष्ट्रीय शक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा, “भारत हमेशा उदार रहा है, लेकिन हमारी उदारता को कभी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।” उन्होंने नागरिकों से तिरंगे को साहस, एकता और आशा के साथ प्रेरणा लेने तथा एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

माननीय उपराष्ट्रपति ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा और ‘हर घर तिरंगा प्रदर्शनी’ का दौरा किया, जिसमें अभियान की भावना तथा राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश प्रदर्शित किया गया था।

इस कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव, पुलिस महानिदेशक श्री रविंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अण्डमान श्री पी. उमर, अध्यक्ष, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद श्रीमती एम. वसंता और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय उप राज्यपाल

ने माननीय उपराष्ट्रपति, भारत गणराज्य के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने के बाद इन द्वीपों की अपनी पहली यात्रा पर आए श्री सी. पी. राधाकृष्णन का गर्मजोशी और सम्मानपूर्वक स्वागत किया। माननीय उप राज्यपाल ने कहा, “हमें इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से गहरा सम्मान प्राप्त हुआ है, जो ‘हर घर तिरंगा’ की भावना और ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ की शाश्वत प्रेरणा का उत्सव मना रहा है।”

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन द्वीपों का एक पवित्र स्थान है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, स्वतंत्रता सेनानियों को इन दूरस्थ तटों पर निर्वासित कर दिया गया, जहां दंडित बस्तियों, एकांत कोठरियों, जबरन श्रम और फांसीघरों ने उनके असाधारण कष्ट और बलिदान को देखा। सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर का कारावास और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया ऐतिहासिक भूख हड़ताल औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि 30 दिसंबर, 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर, 2018 को यहां फ्लैग प्लांट पर 150 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ का अनावरण किया था। इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों पर अब परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए द्वीपों सहित 754 द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज सफलतापूर्वक फहराया गया है, जो एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति की यात्रा उस दूरदर्शी परिवर्तन के साथ हो रही है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप वर्तमान में ‘विकसित भारत’ की दिशा में अपनी ऐतिहासिक यात्रा के रूप में देख रहे हैं। 2 और 3 मई को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और द्वीपों को विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्कूबा डाइविंग केंद्र के रूप में बढ़ावा देने



के उद्देश्य से, 2,400 वर्ग मीटर के विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को पानी के भीतर फहराकर और 22 मीटर ऊंचे पानी के भीतर मानव स्तंभ का निर्माण करके स्कूबा डाइविंग में दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में एक व्यापक बदलाव लाते हुए, इस वर्ष 12 नए स्कूबा डाइविंग स्थलों को खोला गया है, जबकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर चार प्रमुख पर्यावरण-पर्यटन परियोजनाओं के अनुबंध प्रदान किए गए हैं और पूरे द्वीपसमूह में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आतिथ्य सुविधाओं के लिए 11 और परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि हमारी नीली अर्थव्यवस्था की परिकल्पना सतत मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, समुद्री संपर्क, मूल्य संवर्धन और समुद्री संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग को एक साथ लाकर द्वीपों में आजीविका के अवसर पैदा करती है और दीर्घकालिक विकास को गति देती है। अण्डमान ट्रंक रोड को दो लेन का बनाने, पुलों के निर्माण, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण, जहाजरानी सेवाओं तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के माध्यम से संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इन द्वीपों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 50 मेगावाट क्षमता वाले एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि भविष्य की दूरदर्शी

परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, ग्रेट निकोबार द्वीप की परियोजनाएं, जिनमें ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और सहायक बुनियादी ढांचे के घटक शामिल हैं, तथा अटलांटा बे में एक ग्रीनफील्ड बहुउद्देशीय गहरे पानी का बंदरगाह, इन द्वीपों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वार के रूप में स्थापित करेंगे।

इससे पहले, सभा का स्वागत करते हुए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव ने कहा कि आज का राज्य समारोह ‘हर घर तिरंगा’ की भावना का उत्सव मनाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे घरों पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और ‘वंदे मातरम्’ का आह्वान पूरे देश में गूंज रहा है, उसी प्रकार हम मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करने और उन बलिदानों को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को संभव बनाया।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत विशेष स्थान है और राष्ट्रीय ध्वज के साथ इसका गहरा संबंध है। मुख्य सचिव ने कहा कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने ‘हर घर तिरंगा’ की भावना को घरों और बस्तियों से आगे बढ़ाते हुए, केंद्र शासित प्रदेश के दूरस्थ और निर्जन द्वीपों तक तिरंगा पहुंचाया है।

द्वीपों में आज मनेगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त। भारत सरकार एनीमिया मुक्त भारत तथा भारत के बच्चों के कृमि-मुक्त भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। कृमि संक्रमण बच्चों की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। पोषण में कमी का बच्चों की वृद्धि एवं शारीरिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कृमि मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का उपभोग कर लेते हैं तथा रक्त की हानि, कुपोषण और अवरुद्ध शारीरिक वृद्धि का कारण बनते हैं। अधिक कृमि संक्रमण होने पर बच्चे प्रायः इतने अरवस्थ या थके हुए रहते हैं कि वे विद्यालय अथवा आंगनवाड़ी में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते या नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसका दीर्घकालिक नकारात्मक असर पड़ सकता है। अद्ययनों से पता चला है कि नियमित कृमिनाशन से विद्यालयों में अनुपस्थिति की दर कम होती है।

देश में एनीमिया एवं उससे संबंधित बीमारियों के प्रमुख कारण आंतों के कृमियों के संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता

विभाग के समन्वय से पूरे देश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कृमिनाशक गोली दी जाती है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस-2026 (अगस्त चरण) का आयोजन 10 अगस्त, 2026 को किया जाएगा तथा इसके बाद 17 अगस्त, 2026 को मॉप-अप अभियान चलाया जाएगा। इस चरण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को दी जाएगी। सभी अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चों को विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में एल्बेंडाजोल की गोली अवश्य दी जाए।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में आमजन से भी अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस-2026 के अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

रैम्प पर्यटन हस्तक्षेप 2026-27 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने राज्जिंग एंड एक्सेलेरेंसिग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) पर्यटन हस्तक्षेप, 2026-27 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), होमस्टे मालिकों/कर्मचारियों तथा व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना अधिसूचना संख्या 242/2026 दिनांक 5 अगस्त, 2026 के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र (असाधारण) संख्या-243 में अधिसूचित की गई है तथा 6 अगस्त, 2026 के डेली टेलीग्राम समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं: 1. गुणवत्तापूर्ण एवं सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में होमस्टे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम। 2. खगोलीय पर्यटन उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई सहायता के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना।

निर्धारित आवेदन-पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा विस्तृत दिशा-निर्देश ई-राजपत्र पोर्टल <http://andsw1.and.nic.in/doip/index.php/home/srchgazette> (राजपत्र संख्या-243, दिनांक 05.08.2026) पर उपलब्ध हैं। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के अंतर्गत चयनित लाभार्थी आवश्यक खगोलीय पर्यटन उपकरण/दूरबीन खरीद कर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि होमस्टे संचालक/कर्मचारी विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होमस्टे के अध्ययन भ्रमण में भाग ले सकेंगे। इस संबंध में लाभार्थियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकरण एवं सुविधा शिविर आयोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु सुविधा शिविर में भाग लेने के इच्छुक लाभार्थियों से रुचि/सहमति पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र योजना शाखा, पर्यटन निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में 20 अगस्त, 2026 को सायं 5 बजे तक जमा किया जा सकता है।

सभी पीएचएच एवं अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डधारक परिवारों से 15 अगस्त तक आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील

श्री विजय पुरम, 9 अगस्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का शुभारंभ 23 सितंबर, 2018 को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में किया गया था। यह योजना देशभर के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारक सभी परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे सभी पात्र पीएचएच एवं एएवाई लाभार्थी, जिन्होंने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 15 अगस्त, 2026 अथवा उससे पूर्व अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कैशलेस उपचार का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पात्र लाभार्थी गृगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध आयुष्मान ऐप, निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), निकटतम स्वास्थ्य केंद्र अथवा जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम स्थित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहायता काउंटर के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

भारत वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की ओर अग्रसर, रिकॉर्ड घरेलू यात्राओं और बेहतर बुनियादी ढांचे से मिली नई गति

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

भारत वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की ओर अग्रसर, रिकॉर्ड घरेलू यात्राओं और बेहतर बुनियादी ढांचे से मिली नई गति भारत तेजी से दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विविधता, आध्यात्मिक स्थलों, योग और आयुर्वेद जैसी परंपराओं के साथ बेहतर बुनियादी ढांचे, आधुनिक कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं ने देश के पर्यटन क्षेत्र को नई गति दी है। पर्यटन अब केवल घूमने-फिरने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।

सरकार के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 2.9 अरब घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं, जो महामारी-पूर्व स्तर से भी अधिक हैं। वहीं, 2025 में करीब 2.02 करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत पहुंचे, जिससे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर देश की स्थिति और मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 में पर्यटन क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 15.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.22 प्रतिशत है। इस क्षेत्र ने 8.46 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध कराया। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से 31.7 अरब अमेरिकी डॉलर की आय हुई।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। एक ही देश में पर्यटकों को प्राचीन सभ्यताओं की विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र तट, वन्यजीव अभयारण्य, पारंपरिक हस्तशिल्प, विविध व्यंजन, रंग-बिरंगे त्योहार, योग और आयुर्वेद जैसी अनूठी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का अनुभव मिलता है। यही विविधता भारत को वर्षभर पर्यटन के लिए आकर्षक बनाती है। देश में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो इसकी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को दर्शाते हैं।

भारत में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन लगातार विस्तार कर रहा है। काशी, अयोध्या, चारधाम, बोधगया, अमृतसर, तिरुपति और पुरी जैसे धार्मिक स्थल हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही बौद्ध पर्यटन सर्किट भारत को एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार इन स्थलों पर सड़क, रेल और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के साथ आधुनिक सुविधाओं और पर्यटक सेवाओं का भी विस्तार कर रही है। भारत स्वास्थ्य और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से

इतिहास के पन्नों में 10 अगस्त: ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’ के रचयिता श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ की पुण्यतिथि

नई दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)।

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा’ आज भी हर भारतीय के मन में राष्ट्रप्रेम और गौरव की भावना जगाता है। इस कालजयी झंडा गीत के रचयिता स्वतंत्रता सेनानी और कवि श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ की पुण्यतिथि 10 अगस्त को मनाई जाती है। वर्ष 1977 में इसी दिन उनका निधन हुआ था। श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ का जीवन देशसेवा और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पण से जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी लेखनी को राष्ट्रीय चेतना जगाने का माध्यम बनाया। उनके रचे गीतों और कविताओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत ने लोगों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का काम किया। तिरंगे को केंद्र में रखकर रची गई इसकी पंक्तियां स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों में जोश भरती थीं।

श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ केवल कवि ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने सामाजिक जागरूकता और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने लेखन और कर्म, दोनों के माध्यम से योगदान दिया। देश के प्रति उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1973 में पद्म श्री से सम्मानित किया। उनका प्रसिद्ध झंडा गीत आज भी राष्ट्रीय पर्वों और विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों में गूंजता है। महत्वपूर्ण घटनाचक्र—1809— इक्वाडोर को स्पेन से आजादी मिली।

1822— सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 20 हजार लोगों की मौत।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर उपयोगकर्ताओं से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, व्यापारियों के लिए भी अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे मुफ्त

नई दिल्ली, 09 अगस्त (आईएनएस)।

केंद्र सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को स्पष्ट किया कि यूपीआई से भुगतान करने वाले आम नागरिकों से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह नि:शुल्क बने रहेंगे। साथ ही, व्यापारियों के लिए भी यूपीआई के अधिकांश ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भविष्य में यदि व्यापारी छूट दर (एमडीआर) लागू की जाती है, तो यह केवल कुछ सीमित प्रकार के व्यापारी ट्रांजैक्शन पर, एक निश्चित सीमा से अधिक राशि होने की स्थिति में और बेहद मामूली दर पर लागू होगी। यह दर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले शुल्क की तुलना में काफी कम होगी। सरकार ने कहा कि सभी व्यापारियों पर एक समान शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है।

मंत्रालय के अनुसार, कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10ए में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की अध्यक्षता वाली यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति यह तय करेगी कि एमडीआर लागू किया जाना है



आगे बढ़ रहा है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व, हिमालयी क्षेत्रों और जैव विविधता वाले इलाकों में इको-टूरिज्म तथा वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

सरकार पर्यटन को अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार बनाने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और जिम्मेदार यात्रा व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग, समुद्री पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर पर्यटकों को पारंपरिक स्थलों से आगे नए पर्यटन केंद्रों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का दबाव कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिल सकती है।

सरकार का मानना है कि भारत का पर्यटन क्षेत्र केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। लक्ष्य ऐसा पर्यटन तंत्र विकसित करना है, जो आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करे। इसके लिए पर्यटन स्थलों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं, कौशल विकास और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं पर लगातार निवेश किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्यटन क्षेत्र में विकास की यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल दुनिया के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है, बल्कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार, निवेश और समावेशी आर्थिक विकास का वैश्विक उदाहरण भी बन सकता है। सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का संगम भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।



1831— कैरेबियाई द्वीप समूह बारबाडोस में चक्रवाती तूफान से डेढ़ हजार लोगों की मौत।
1966— अमरीका ने अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने की लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने पहला अंतरिक्ष यान भेजा।
1962— आज ही के दिन बच्चों का चहेता स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया।
1979— उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 को प्रक्षेपित किया गया।
1990— तकरीबन 15 महीने की यात्रा के बाद अमेरिका का अंतरिक्ष यान मगैलन शुक्र ग्रह पर पहुंचा और उतरने के कुछ ही देर बाद उसका केलिफोर्निया स्थित संचालन केन्द्र से संपर्क टूट गया।
2006— तमिल विद्रोहियों पर फौजी कार्रवाई में श्रीलंका में 50 नागरिक मारे गये।
2008— चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स बैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया।
2010— भारत ने 2010 में उपग्रह स्थिति तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया।



या नहीं और यदि लागू होता है तो उसकी दर क्या होगी। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस एक्ट) में हालिया संशोधन को लेकर कुछ गलत धारणाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों द्वारा इसे आम नागरिकों से यूपीआई शुल्क वसूलने की दिशा में कदम बताया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह संशोधन एक सक्षमकारी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी विकास, वित्तीय समावेशन और उभरते जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।

बयान में आगे कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और डिजिटल ढांचे को लगातार उन्नत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत है। इसके लिए एक ऐसा आर्थिक ढांचा आवश्यक है, जिससे यूपीआई भविष्य में भी मजबूत और विश्वसनीय बना रहे।

खेल मंत्री ने ‘नशामुक्त भारत’ संदेश के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 85वें संस्करण का किया नेतृत्व

हणोल (गुजरात), 09 अगस्त (हि.स.)।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार को गुजरात के हणोल से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 85वें संस्करण का नेतृत्व किया। इस अवसर पर युवाओं, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े प्रतिभागियों ने ‘नशामुक्त भारत’ का सामूहिक संकल्प लिया। अभियान का संदेश रहा— ‘फिटनेस को हां कहें, ड्रग्स को ना कहें।’

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए फिटनेस को स्वस्थ जीवनशैली के सकारात्मक विकल्प के रूप में बढ़ावा देना था।

डॉ. मांडविया ने संडे ऑन साइकिल को जन आंदोलन बताते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि यह पहल प्रधानमंत्री के फिट इंडिया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। देशभर में 10,000 से अधिक स्थानों पर युवाओं ने साइकिलिंग के माध्यम से यह संदेश दिया है।” डॉ. मांडविया ने दिसंबर 2024 में संडे ऑन साइकिल की शुरुआत की थी। इसके बाद से पूरे देश में 30 लाख से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले चुके हैं।

दिल्ली में इसका मुख्य कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सामूहिक ‘नशामुक्त भारत’ संकल्प रहा, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने नशे से मुक्त जीवन जीने

सरकार ने समुद्री प्रशासन को डिजिटाइज करने और नाविकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया ‘ई—समुद्र’ प्लेटफॉर्म

मुंबई, 09 अगस्त (आईएनएस)।

केंद्र सरकार ने शनिवार को समुद्री क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को गति देने और नाविकों के कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘ई—समुद्र’ नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की समुद्री विकास रणनीति के केंद्र में नाविक रहेंगे और सरकार उनकी सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हर भारतीय नाविक सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित होना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता है।

मंत्री ने बताया कि भारत आज दुनिया में नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत वर्तमान में विश्व का अग्रणी शिप रीसाइक्लिंग हब है और सरकार देश को दुनिया के शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।

मंत्री ने कहा कि ई—समुद्र केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह समुद्री प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और हितधारक—केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने बताया कि ई—समुद्र समुद्री सेवाओं के लिए एक सिंगल डिजिटल विंडो के रूप में काम करेगा। इसके जरिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, रियल-टाइम ट्रेकिंग और

भारत ने गैर—जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया

नई दिल्ली, 09 अगस्त । भारत ने गैर—जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई यह उपलब्धि, वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में

ओटीपी क्यों आता है? फोन पर आने वाले इस 6 अंकों के नंबर का क्या है असली काम

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

OTP का पूरा नाम One-Time Password है। यह कुछ अंकों या अक्षरों का एक खास कोड होता है, जो सिर्फ एक बार और लिमिटेड टाइम के लिए मान्य रहता है। आमतौर पर यह 4, 6 या 8 अंकों का होता है और SMS, ईमेल या ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भेजा जाता है।

ओटीपी का सबसे बड़ा मकसद आपकी पहचान की जांच करना और आपके अकाउंट को सेक्योर रखना है। मान लीजिए किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया। अगर केवल पासवर्ड से ही लॉगिन हो जाता, तो वह आसानी से आपके अकाउंट में घुस सकता था। लेकिन ओटीपी आने पर उसे आपके मोबाइल या ईमेल तक भी पहुंच चाहिए होगी। यही एक्स्ट्रा सुरक्षा आपके अकाउंट को और ज्यादा सेक्योर बनाती है। इस वजह से बैंक, UPI ऐप, ई—कॉमर्स वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओटीपी का यूज करते हैं।

जब हम कोई जरूरी काम करते हैं, जैसे— बैंक अकाउंट में लॉगिन, ऑनलाइन पेमेंट, नया पासवर्ड बनाना, मोबाइल नंबर बदलना, नया डिवाइस जोड़ना, तो सिस्टम एक यूनिक OTP बनाता है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर सेंड कर देता है। अगर आप सही ओटीपी डालते हैं, तो सिस्टम मान लेता है कि यह काम सही व्यक्ति ही कर रहा है। इसके बाद ही प्रोसेस पूरा होता है।

ओटीपी कुछ मिनट बाद अपने आप बेकार हो जाता है। ऐसा सिम्युलेटी के मकसद से किया जाता है। अगर ओटीपी लंबे समय तक वैलिड रहे, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ज्यादातर ओटीपी सिर्फ 30 सेकंड से 10 मिनट के अंदर यूज किए जा सकते हैं।

बैंक और साइबर सुरक्षा एजेंसियां अक्सर कहती हैं— ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर न करें। अगर कोई शख्स आपका ओटीपी जान लेता है, तो वह आपके बैंक



और अपने परिवार, दोस्तों तथा समुदाय को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

रविवार सुबह 5.30 बजे तक 1000 से अधिक लोग स्टेडियम पहुंच गए थे। प्रतिभागियों ने योग और जुंबा जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके बाद इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास पांच किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में कैरम, शतरंज, लूडो और बैडमिंटन के लिए गेम जोन भी बनाया गया। इसके अलावा रस्साकशी और बाधा दौड़ जैसी फिटनेस गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

कार्यक्रम में अभिनेता एवं मॉडल सिद्धार्थ निगम, अंतरराष्ट्रीय स्ववेश खिलाड़ी और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन गुरवीर सिंह, फिट इंडिया एंबेसडर नरेंद्र कुमार और फिट इंडिया चैंपियन एवं प्रसिद्ध जुंबा प्रशिक्षक मीनल पाटक ने भी हिस्सा लिया।

सरकार ने समुद्री प्रशासन को डिजिटाइज करने और नाविकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया ‘ई—समुद्र’ प्लेटफॉर्म



डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा, ई—समुद्र एंड—टू—एंड डिजिटल वर्कफ्लो, ऑनलाइन भुगतान, रियल—टाइम ट्रेकिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट्स के साथ समुद्री सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देगा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सक्रिय नाविकों की संख्या वर्ष 2013 में लगभग 1.03 लाख थी, जो बढ़कर 2025 में 3.23 लाख से अधिक हो गई है। नाविकों की इस तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल सेवाओं और कल्याणकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।

सरकार ने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, भारतीय नौसेना और अन्य एजेंसियों के सहयोग से संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे 4,000 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया। गौरतलब है कि ई—समुद्र और अन्य डिजिटल पहलें मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा हैं।—आईएनएस

भारत ने गैर—जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया

गैर—जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा है कि 2025—26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन—रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई।

ओटीपी क्यों आता है? फोन पर आने वाले इस 6 अंकों के नंबर का क्या है असली काम

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।



खाते, UPI, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सकता है। आजकल साइबर टग खुद को बैंक अधिकारी, कूरियर एजेंट, CBI अधिकारी, कस्टम अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों से OTP पूछते हैं। इसलिए ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए।

OTP सुरक्षा की एक मजबूत परत है, लेकिन यह अकेले हर तरह के साइबर हमले को नहीं रोक सकता। इसलिए मजबूत पासवर्ड, डबल लेयर सिम्युरिटी, ऑफिशियल ऐप का यूज और अवेयरनेस भी जरूरी है।

भारत में हर महीने 5.5 अरब (550 करोड़) से ज्यादा OTP SMS भेजे जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा OTP मार्केट हैं। भारत के लगभग 90% बैंक और फिनटेक कंपनियां SMS OTP को डिफॉल्ट दूसरे सुरक्षा स्तर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यानी ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में ओटीपी सबसे अहम सुरक्षा परत है।

भारतीय नियुर्बैक, डिजिटल लेंडर और फिनटेक कंपनियां हर महीने 200 करोड़ से ज्यादा ओटीपी भेजती हैं। इनमें UPI, नेट बैंकिंग, KYC, ई—मेंटेट और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े ओटीपी शामिल हैं।

आंकड़ों के अनुसार, भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों में ओटीपी से जुड़े फ्रॉड सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ओटीपीस्कैम कुल साइबर फ्रॉड मामलों के एक—चौथाई (25% से अधिक) के लिए जिम्मेदार थे।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान—केन्द्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 8—9 वर्षों में 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां ललित होटल में आयोजित डिजिटल उपकरण पुरस्कार कार्यक्रम में मीडिया से कहा, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो पहले लगभग शून्य थी अब लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गई है और तेजी से विस्तार कर रही है। अगले आठ से नौ वर्षों में इसके 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि साल 2047 के लिए एक ऐसे देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी जिसकी क्षमताओं और नवाचारों को अन्य देश अपना सकें। मंत्री ने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगी। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास जैव प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित नीति है। हमारे पास राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारतीय एआई मिशन भी हैं और हमने अंतरिक्ष और अन्य अग्रणी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है।

परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम से नए अवसर

15 अगस्त पर तिरंगा फहराया जाता है या होता है ध्वजारोहण? लोग आज भी नहीं जानते सही जवाब

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का अवसर होता है. इसी दिन वर्ष 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी. स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में तिरंगा लहराया जाता है और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं. हालांकि हर साल इस अवसर पर एक सवाल जरूर सामने आता है कि इस दिन तिरंगा फहराया जाता है या ध्वजारोहण किया जाता है.

कई लोग ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने को एक ही प्रक्रिया मान लेते हैं, जबकि दोनों में स्पष्ट अंतर है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने का तरीका अलग होता है. यही अंतर इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों के ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है. आइए जानते हैं कि 15 अगस्त को कौन—सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है.

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर रस्सी के माध्यम से खींचते हैं. इसके बाद तिरंगा पूरी तरह खुलकर लहराता है. इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में ध्वजारोहण (Flag Hoisting) कहा जाता है. यह भारत की आजादी और नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक माना जाता है. वर्ष 1947 में पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा इसी तरह फहराया गया था.

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ऊपर बंधी हुई स्थिति से खोलते हैं. इस प्रक्रिया को ध्वज फहराना/(Flag Unfurling) कहा जाता है. यह व्यवस्था

अश्मिता चालिहा ने विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीता

नई दिल्ली, 09 अगस्त |भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है । फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियान शी को तीन गेमों के मुकाबले में 14–21, 21–14, 21–14 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जोरदार वापसी की और 53 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह अश्मिता का पहला बीडब्ल्यूएफ खिताब है।

इससे पहले, अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को 21–13, 16–21, 21–13 से हराकर

कहीं बर्फ तो कहीं समुद्री नजारे, देश के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए घूम सकते हैं ये 5 जगहें

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

रेगिस्तान, रेनफॉरेस्ट और ऊंचे पठारों से घिरा भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर के ट्रॉपिकल द्वीपों तक फैला हुआ है। भारत में कई ऐसी छिपी हुई जगहें हैं, जो मैप के कोने में मौजूद हैं। इन जगहों की खासियत भौगोलिक स्थिति, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत, अनोखी और दूर—दराज जगहों पर समय बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के माणा से लेकर ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट तक, ऐसी ही 5 जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

इंदिरा कोल, लद्दाख— सियाचिन ग्लेशियर के पास पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां और ग्लेशियरों से घिरी यह जगह देश के सबसे दूर—दराज इलाकों में से एक है। यहां पर पर्यटकों के लिए पहुंचना मुश्किल है क्योंकि यह संवेदनशील इलाका है जहां सिर्फ भारतीय सेना के जवान रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। महत्वपूर्ण जगह— भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर के करीब स्थित, बहुत ऊंचाई वाला इलाका, सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आईलैंड। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह जगह हिंद महासागर के खूबसूरत नजारे और लाइटहाउस के लिए जानी जाती है। साल 2004 में आई सुनामी की वजह से यहां की जमीन धंस गई जिससे लाइटहाउस का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। देखने लायक जगह— भारत का दक्षिण पॉइंट, ऐतिहासिक लाइटहाउस, ग्रेट निकोबार की जैवविविधता, हिंद महासागर के नजारे।

किबिथू, अरुणाचल प्रदेश— अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में स्थित किबिथू भारत के सबसे पूर्वी आबादी वाली जगहों

तो पैदा होते हैं लेकिन उद्योग जगत को उभरते क्षेत्रों के लिए खुद को तैयार करने और आवश्यक क्षमताएं विकसित करने की भी आवश्यकता है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास यह दर्शाता है कि नवाचार अब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कुछ युवा उद्यमी छोटे शहरों से भी उभर रहे हैं।

डॉ. सिंह ने अप्रचलित कानूनों और प्रक्रियाओं को हटाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 2,000 अप्रचलित कानूनों को हटा दिया गया है, जिनमें समाज और शासन में बदलाव के बावजूद पूर्ववर्ती युग से चले आ रहे प्रावधान शामिल थे।



भारत के संविधान लागू होने और स्थापित गणतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है. इसलिए 26 जनवरी को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्वतंत्रता दिवस से अलग होती है.

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया. वहीं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना. यही कारण है कि दोनों अवसरों पर ध्वज प्रदर्शन की परंपरा भी अलग—अलग रखी गई है. यह अंतर केवल तकनीकी नहीं बल्कि भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है.

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही राष्ट्रीय गौरव के पर्व हैं, लेकिन इनकी परंपराएं अलग हैं. ध्वज संहिता के अनुसार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री Flag Hoisting करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति Flag Unfurling करते हैं. इस अंतर की सही जानकारी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और इतिहास को समझने में मदद करती है.

कृतज्ञ राष्ट्र ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ और ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ की वर्षगांठ पर अमर सेनानियों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने रविवार को ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ और ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ की वर्षगांठ पर राष्ट्रनायकों तथा अमर सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में भाग लेने वाले सभी लोगों को याद करते हुए, उनका साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर, ‘भारत छोड़ो’ के आह्वान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के हमारे लोगों के अटूट संकल्प को दर्शाया।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि महात्मा गांधी का करो या मरो का आह्वान उस दौर में करोड़ों भारतीयों के लिए साहस और संकल्प की आवाज बना। इस आंदोलन में असंख्य ज्ञात—अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल यातनाएँ सहीँ, संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता के अमृतकाल में उन महान सेनानियों का स्मरण हमें यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को निरंतर मजबूत करते रहें।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस आंदोलन ने देशवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए ‘करो या मरो’ का संकल्प और अदम्य साहस प्रदान किया। अगस्त क्रांति का यह दिन हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए स्वदेशी को अपनाने, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की प्रेरणा देता है। वहीं ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ स्वतंत्रता संग्राम का वह अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को नई ऊर्जा दी। चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के

डॉ. अम्बेडकर योजना के तहत 385 मामलों में लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई— केंद्र

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतर—जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत योजनाओं को 31 मार्च, 2023 से केंद्र प्रायोजित योजना के साथ विलय कर दिया गया है। वहीं, लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पहल की गई, 385 अंतर—जातीय विवाह के मामलों में लगभग ६9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठवले ने डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के जवाब में यह जानकारी दी। दरअसल, योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचने के लिए ‘डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर—कास्ट मैरिजज’ और ‘डॉ. अम्बेडकर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज स्कीम’ का 31 मार्च, 2023 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया।

दिन में सूर्यग्रहण, रात में गिरेंगे उल्कापिंड... खगोलीय इतिहास के लिए ऐतिहासिक होगा 12 अगस्त

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

12 अगस्त, 2026 की तारीख दुनिया भर के खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए बेहद खास बनने जा रही है। सुबह सूरज उगने से ठीक पहले छह ग्रहों की कतार दिखेगी, दिन में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और रात में टूटे हुए तारों यानी पर्सिड उल्कापिंडों की आतिशबाजी होगी। खगोलविदों का कहना है कि इन तीनों घटनाओं का एक ही तारीख पर होना एक बहुत दुर्लभ संयोग है।

12 अगस्त को सूरज निकलने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले आसमान में छह ग्रह, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक लाइन में फैले हुए दिखाई देंगे।

इनमें से मंगल, बृहस्पति और शनि को बिना किसी उपकरण के नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए बाइनोकुलर्स या टेलिस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दिन के समय एक बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यह 1999 के बाद यूरोप के मुख्य इलाके से दिखने वाला पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।

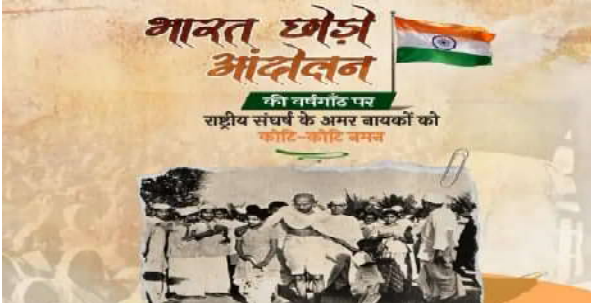
योग करने वालों में तंबाकू छोड़ने की संभावना 50% तक बढ़ी, एम्स की स्टडी में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

नई दिल्ली, 09 अगस्त ।

योग का अभ्यास करने से तंबाकू का प्रयोग करने वालों की उसके छोड़ने की संभावना में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। साथ ही यह चिंता, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक कारकों को भी कम कर सकता है जो नशे से जुड़े होते हैं। यह जानकारी एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है।

यह व्यस्थित समीक्षा और मेटा विश्लेषण, जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया, जर्नल निकोटीन एंड तंबाकू रिसर्च में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में पाया गया कि योग का अभ्यास करने वाले तंबाकू के उपयोगकर्ताओं की तंबाकू से अस्थायी रूप से दूर रहने की संभावना उन नियंत्रण समूहों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक थी, जिन्हें मानक हस्तक्षेप या अन्य गैर—योग दृष्टिकोण प्राप्त हुए। लेखकों ने लिखा, समीक्षा के नतीजों से पता चलता है कि तंबाकू छोड़ने के लिए योग एक काफी असरदार (लगभग 50%) उपाय हो सकता है।

यह समीक्षा एम्स दिल्ली की डॉ. श्रुति सिंह, धनलिका, पार्थ हन्दर और गौतम शर्मा द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने अमेरिका, भारत और थाईलैंड के 629 प्रतिभागियों के साथ सात रैंडम नियंत्रित परीक्षणों के साक्ष्य का विश्लेषण किया। इनमें से पांच अध्ययनों को मेटा—विश्लेषण में शामिल किया गया। तंबाकू का इस्तेमाल दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिससे हर साल लगभग 87 लाख लोगों की मौत होती है। कई इस्तेमाल



नेतृत्व में वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और समर्पण से इस एक्शन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को यह बता दिया कि इस देश के संसाधनों पर देशवासियों का ही अधिकार है। देश काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी अमर क्रांतिकारियों का सदैव ऋणी रहेगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सन 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की शुरुआत की थी।

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस आंदोलन ने देशभर में नई चेतना का संचार किया और असंख्य भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी, सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के त्याग, तप और संघर्ष से मिली स्वतंत्रता इस देश की महान राष्ट्रीय विरासत है। आज उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत की आज़ादी में वीर सेनानियों का योगदान एक अमूल्य विरासत है। केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर उनके सपनों का सशक्त एवं समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लें।

तहत 385 मामलों में लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई— केंद्र

इन दोनों योजनाओं का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के साथ विलय कर दिया गया था।

चूंकि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की उक्त योजनाओं का 31 मार्च, 2023 से विलय कर दिया गया था, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इन श्रेणियों के तहत राज्यवार लंबित आवेदनों का प्रश्न ही नहीं उठता।

शनिवार को एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू की जाती है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उन्हीं की है।